तिब्बत देश

तिब्बत में चीन की टूरिस्ट नीति की असली कूटनीति

तिब्बत के मामले में चीन सरकार ने पिछले तकरीबन एक दशक से एक नई रणनीति अपनायी है। इस नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि तिब्बती के भीतर वहां की संस्कृति और तिब्बती पहचान के बारे में तिब्बती जनता के साथ भले ही जो नीति अपनायी जाए लेकिन इससे जो फायदा उठाया जा सकता है वह जरूर उठाया जाए। इस नीति में तिब्बत को विदेशी पर्यटकों के लिए खोलने का फैसला भी शामिल था। इससे पहले तकरीबन पचास साल तक चीन विदेशियों को तिब्बत से परे रखने के हर तरह के हथकंडे अपनाता रहा है।

पिछले सात–आठ साल के दौरान सामने आने वाले परिणाम यह दिखाते हैं कि यह रणनीति काफी हद तक कामयाब रही है। कुछ सप्ताह पहले चीन के पर्यटन ब्यूरों ने तिब्बत में पर्यटन के बारे में आंकड़े जारी करते हुए बताया कि पिछले साल तिब्बत में 3 लाख 65 हजार विदेशी पर्यटक आए जो पिछले साल का 122 प्रतिशत था। पहले विदेशी पर्यटकों में अमरीकियों की संख्या सबसे अधिक होती थी पर बीते साल में जापानी पर्यटकों ने पांच गुना से भी ज्यादा संख्या में आकर अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। इनके अलावा कई देशों से आने वाले बौद्ध पर्यटकों की संख्या भी काफी बड़ी है। खुद चीनी पर्यटकों की संख्या बीते साल चालीस लाख से ज्यादा रही। (ताइवान से बौद्ध आस्था के कारण भारी संख्या में तिब्बत में आने वाले पर्यटकों को चीन सरकार 'चीनी' नागरिकों में ही गिनती है।) आने वाले साल में पर्यटकों की कुल संख्या पचास लाख से ज्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में लगता है कि चीन सरकार ने एकदम व्यवहारिक नीति अपनाते हुए तिब्बत के बारे में उस अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता और उत्सुकता का अच्छा फायदा उठाया है जो पिछले पचास साल से दलाई लामा और तिब्बत के अंतर्राष्ट्रीय मित्रों के प्रयासों से चलने वाले तिब्बत समर्थक आंदोलन से पैदा हुई है।

तिब्बत के पर्यटन को लेकर चीन के सरकारी प्रचार में बार–बार इस बात का दावा किया जाता है कि चीन सरकार तिब्बत की सांस्कृति निधि की रक्षा के लिए बहुत भारी खर्चा कर रही है। इस बारे में आए दिन यह बताया जाता है कि ल्हासा में दलाई लामा के महल पोताला पैलेस और नोरबुलिंका तथा वहां के एक महत्वपूर्ण ध ार्मिक केंद्र साक्या मठ की मरम्मत पर 33.3 करोड़ युआन यानी तकरीबन 225 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यह काम 2002 से चल रहा है।

ये आंकड़े बताते हुए चीन सरकार दुनिया को यह दिखाने की कोशिश करती है कि वह तिब्बत की संस्कृति को बचाए रखने के बारे में बहुत उत्सुक है। ऐसा करने के पीछे उसका एक बड़ा दरादा दुनिया का ध्यान इस बात से हटाना है कि इससे पहले के पचास साल के दौरान चीन ने तिब्बत की संस्कृति, धार्मिक व्यवस्था और तिब्बती राष्ट्रीय पहचान को बरबाद करने का कोई भी हथकंडा बिना इस्तेमाल किए नहीं छोड़ा है। अपने इस प्रोपेगेंडा में वह इस कड़वी सच्चाई को भी डकार जाती है कि तिब्बती जनता की धार्मिक आस्थाओं को खत्म करने के अभियान में वहां के कम से कम साढ़े छह हजार मठों और मंदिरों में से छह हजार से ज्यादा को कभी का बरबाद किया जा चुका है। जिन मठों के विशाल आकार की वजह से उनके भवनों को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं था उन्हें 1960–70 वाले दशक में 'सांस्कृतिक क्रांति' के दौरान और बाद में भी फौजी बैरको और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालयों में बदल दिया गया था। इसके अलावा वहां की धार्मिक गतिविधियों को पूरी तरह बंद करके वहां के लामाओं को भी लेबर कैंपों में भेज दिया गया था।

तिब्बत की सांस्कृतिक विरासत पर छह साल में 225 करोड़ रु के अपने इस भारी खर्चे की डींग मारते समय चीन का प्रोपेगेंडा विभाग इस बात को गोल कर जाता है कि तिब्बत के पर्यटन से उसे केवल पिछले एक साल के दौरान ही 4.85 अरब युआन यानी तकरीबन 3400 करोड़ रु की आमदनी हुई है। चीन के पर्यटन विभाग के अनुसार अगले साल में यह लाभ तकरीबन 4200 करोड़ रु होगा।

लेकिन यह मान लेना बहुत नौसिखियापन होगा कि तिब्बत में पर्यटन को बढ़ावा देने के पीछे चीन का असली मकसद पैसा कमाना है। दरअसल तिब्बत पर पचास साल तक गैरकानूनी कब्जा जमा कर उसे दुनिया की आंखों से छिपा कर रखने के बाद अब अचानक तिब्बत के दरवाज़े खोलने के पीछे चीन सरकार का कहीं बड़ा इरादा कुछ खास तरह से राजनीतिक लाभ उठाना है। पहला तो यह कि लगातार बंद दरवाज़ों को खोलकर अब चीन दुनिया यह बताने की कोशिश कर रहा है कि तिब्बत में सब कुछ ठीक ठाक है और हालात चीन के नियंत्रण में हैं। दूसरे, तिब्बत को पर्यटकों के लिए खोलने से पहले तिब्बत के चुनिंदा इलाकों में भारी पैमाने पर विकास करके चीन सरकार शानदार सड़कों, आधुनिक भवनों और लकदक चमकते मॉल्स तथा बाजार के माध्यम से दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को यह दिखा रही है कि तिब्बत की जनता दलाई लामा के जमाने के पिछड़ेपन में नहीं रह रही बल्कि समृद्धि के एक नए युग में जी रही है। तिब्बती और चीनी चेहरों में फर्क कर पाने में असर्थक पर्यटक कभी समझ ही नहीं पाते कि ये सब सुविधाएं चीन से लाकर बसाए गए लाखों हान चीनियों को वहां बनाए रखने के लिए हैं। गांवों में तिब्बती जनता की असली गरीबी को देखने का मौका पर्यटकों को कभी मिल ही नहीं पाता।

इसमे शक नहीं कि तिब्बतियों को ल्हासा और शिगात्से के बड़े मंदिरों में दर्शन की छूट है। लेकिन पर्यटक यह नहीं जानते कि मंदिरों में तिब्बतियों को जाने की केवल तभी छूट है जब वे अच्छे कपड़े पहने हों। बरसों बाद मिली छूट के बाद सैंकड़ों किलोमीटर दूर से आए और नए परंपरागत कपड़ों में सजेधजे तिब्बती श्रद्धालुओं के फोटो खींचते हुए पर्यटकों को तो यही लगता है कि चीनी राज में तिब्बती समृद्ध भी हैं और धार्मिक रूप से आजाद भी। पर्यटकों को कभी नहीं पता चल पाता कि गिने चुने मठों में रहने वाले गिने चुने लामाओं को किस तरह के सरकारी नियंत्रण में रहना पड़ता है।

इसी तरह ल्हासा तक चीनी रेलगाड़ी लाकर चीन दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह तिब्बती जनता के कल्याण पर कितना भारी खर्च कर रहा है। लेकिन एअर कंडीशंड और आक्सीजन के केबिन के बाहर की असली तिब्बती जिंदगी को पर्यटक कभी नहीं देख पाते। उन्हें कभी यह भी नहीं पता चल पाता कि इसी पटरी पर चलने वाली सामान्य रेलगाड़ियां लाखों चीनियों को लाकर तिब्बत में बसा रही हैं और हर दिन तिब्बत के करोड़ों डालर के बेशकीमती खनिजों को लूटकर चीन ले जा रही हैं। तिब्बत में चीन के असली इरादों को समझने के लिए चीन की इस टूरिस्ट नीति की असली कूटनीति को समझना बहुत जरूरी है।

– विजय क्रान्ति

चीन में कुछ राजनीतिक 'अपराधियों' को मौत की सजा : आतंक का शासन

मानवाधिकारों के सवाल पर आलोचना से चीन सरकार परेशान

आलोचकों पर चीन सरकार का पलटवार

बीजिंग को चुनते समय ओलंपिक समिति ने आश्वासन दिया था कि यह जिम्मेदारी मिलने से चीन सरकार को चीन में मानवाधिकारों के हालात सुधारने का प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन उलटे इसमें और खराबी आने पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन यह सवाल अब फिर उठा रहे हैं।

बीजिंग, 08 जनवरी दुनिया भर में मानवाधिकारों के बारे में चीन की आलोचना से तिलमिलायी चीन सरकार चीन ने तिलमिलाहट भरी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उसने ऐसी आलोचना करने वालों पर यह कहते हुए आज निशाना साधा कि दुनिया के कुछ देश बीजिंग ओलम्पिक की आड़ में यहां की सरकार को खलनायक दर्शाना चाहते हैं।

मानवाधिकार संगठनों ने चीनी आंदोलनकारी नेता हु जिया को पिछले माह गिरफ्तार किये जाने की निंदा की है, लेकिन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जियांग यू ने इन आरोपों का खंडन किया कि चीन ओलम्पिक खेलों से पहले दमनात्मक कार्रवाई पर उतर आया है। हु जिया पर आरोप लगाया गया है कि वह सरकार के विरुद्ध लोगों को भड़काने का काम करते हैं।

सुश्री जियांग ने नियमित संवाददाता सम्मेलन में बताया, ''कुछ संगठन और व्यक्ति चीन को दुनिया के समक्ष खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए बीजिंग ओलम्पिक का सहारा ले रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इससे ओलम्पिक खेलों की भावना को ठेस पहुंचती है।''

चीन सरकार दुनिया भर में चले उस आंदोलन से बहुत परेशान है जिसके तहत मानवाधिकार संगठन और लोकतंत्र समर्थक लोग अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से यह मांग कर रहे हैं कि अगर चीन सरकार अपने नागरिकों को उनके मूलभूत मानवाधिकार देने की गारंटी नहीं देती तो चीन से ओलंपिक खेलों की मेजबानी वापस ले लेनी चाहिए। बीजिंग को 2008 के ओलंपिक खेलों के लिए चुने जाते समय इस आलोचना के संदर्भ में ओलंपिक समिति ने आश्वासन दिया था कि यह जिम्मेदारी मिलने से चीन सरकार को चीन में मानवाधिकारों के हालात के सुधारने का प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन उलटे इसमें और खराबी आने के कारण अंतर्राष्ट्रीय संगठन यह सवाल अब खुलकर उठा रहे हैं।

खुद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने चीन सरकार से अनुरोध किया है कि वह खेलों की कवरेज करने के लिए आने वाले विदेशी संवाददाताओं पर लगाई गई पाबंदियों को ढीला करे। इनमे से एक नियम के मुताबिक किसी भी विदेशी टीवी चैनेल के सिग्नल को सीधे प्रसारित करने की अनुमति नहीं होगी। प्रसारण से पहले चीनी अधिकारी कम से कम छह मिनट तक इस फुटेज की जांच करने के बाद ही इसके प्रसारित करने की अनुमति देंगे।

लेकिन इस मामले में चीन की आलोचना केवल विदेशी मानवाधिकार संगठन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद चीन के बुद्धिजीवी भी यह सवाल उठा रहे हैं। पिछले दिनों चीन के वकीलों, शिक्षाविदों, संपादकों और लेखकों के एक समूह ने एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर कर हु की गिरफ्तारी की निंदा की है और सरकार से बीजिंग ओलम्पिक से पहले यहां मानवाधिकारों की स्थिति को सुधारने की अपील की है।

चौंतीस वर्षीय हु एड्स पीड़ितों की वकालत को लेकर पहली बार चर्चा में आए थे। उन्होंने मानवाधिकार अधिवक्ता गाओ झिशेंग और नागरिक अधिकारों से जुड़े चेन गुआंगचेंग और अन्य के मुकदमों की सुनवाई के बारे में ईमेल के जरिये पत्रकारों को अवगत कराया।

चीनी पुलिस ने हु की पत्नी, जेंग जिनयान उनके नवजात शिशु और जेंग की वृद्ध मां को बीजिंग स्थित आवास छोड़ने से रोक दिया है। लेकिन सुश्री जियांग ने चीन की न्यायिक प्रणाली का बचाव किया है। उन्होंने कहा, ''कानून के अनुसार चीन सरकार अपने नागरिकों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की रक्षा करती है। आपको कानून के तहत तभी सजा मिलती है, जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं।''

प्रवक्त ने इन रिपोर्टों को गलत बताया कि चीनी अधिकारी तिब्बतियों को उस आवेदन पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य कर रहे हैं जिसमें तिब्बत के पूर्व शासक और अध्यात्मिक गुरू दलाई लामा की तिब्बत वापसी का विरोध किया गया है। चीन परमपावन दलाई लामा को 'देशद्रोही' मानता है।

दलाई लामा के सवाल पर चीन सरकार और तिब्बती जनता के बीच टकराव जारी

दलाई लामा की वतन वापसी के विरोध के लिए तिब्बतियों पर दबाव

बीजिंग चीनी अधिकारी परमपावन दलाई लामा की वतन वापसी के खिलाफ आवेदन पर हस्ताक्षर के लिए तिब्बतियों को मजबूर कर रहे हैं। यह जानकारी लंदन स्थित एक तिब्बत समर्थक संगठन फ्री टिबेट कैंपेन ने दी है। चीन सरकार ऐसा करके दुनिया को यह दिखाने का प्रयास कर रही है कि तिब्बत की जनता दलाई लामा का विरोध करती है और वह नहीं चाहती कि चीन सरकार उन्हें तिब्बत आने का निमंत्रण दे। यहां यह जानना महत्वपूर्ण है कि दुनिया के कई देश चीन सरकार पर इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि वह दलाई लामा को बातचीत के लिए अपने यहां आमंत्रित करे और उन्हें तिब्बत जाने की भी आजादी दे।

संगठन ने कहा है कि चीन का यह कदम तिब्बत के पूर्व शासक और अध्यात्मिक नेता दलाई लामा की लोकप्रियता पर अंकुश लगाने के लिए और उन्हें अमरीका द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिये जाने के विरोधस्वरूप उठाया गया है।

अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश ने गत वर्ष अक्टूबर में परमपावन दलाई लामा को वाशिंगटन में अमेरिकी संसद के कांग्रेशनल गोल्ड मैडल से सम्मानित किया था, जिसकी वजह से चीन का गुस्सा सातवें आसमान पर है। इससे पहले सितम्बर में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भी परमपावन दलाई लामा को सम्मानित किया था।

पिछले कुछ साल से चीन सरकार और दलाई लामा की निर्वासन सरकार के बीच बातचीत शुरू करने के लिए संपर्क चल रहा है पर इसके कोई रचनात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं।

फ्री टिबेट कैम्पेन की कार्यवाहक निदेशक एन्नी होम्स ने एक ई–मेल में कहा है, ''चीनी अधिकारी वास्तव में दलाई लामा के विरुद्ध दुष्प्रचार अभियान को तेज करने में लगे हुए हैं।'' इस बारे में पूरे तिब्बत के मठों में रहने वाले भिक्षुओं और भिक्षुणियों को ऐसे बयान जारी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिनमें दलाई लामा की आलोचना की गई होती है।

पिछले साल दलाई लामा ने तिब्बत में रहने वाले तिब्बती नागरिकों से अपील की थी कि वे जानवरों की खाल वाले कपड़े न पहनें। इस पर इस इलाके में ऐसे कपड़ों की जगह–जगह होली जलाई गई जिसे दलाई लामा का समर्थन मानते हुए चीन ने इस पर प्रतिबंध लगाने की असफल कोशिश की थी।

गत दिसम्बर में तिब्बतियों की घनी आबादी वाले गांसु प्रांत के लिथांग कस्बे में एक सर्वाजनिक समारोह के दौरान वहां के निवासियों से कहा गया कि यदि वह दलाई लामा की वतन वापसी के खिलाफ हैं तो अपने हाथ उठाएं। कैंपेन के अनुसार, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया।

फ्री टिबेट कैम्पेन ने बताया कि उसके बाद वहां के निवासियों से कहा गया कि यदि उनके घरों में हथियार नहीं हैं तो वे लोग हाथ उठाएं। चूंकि चीनी कानून में घर पर हथियार रखना अपराध है इसलिए सभी ने अपने हाथ उठा दिए। इसकी एक तस्वीर लेकर उसे सरकारी मीडिया में भेज कर समाचारों में यह दावा किया गया कि तिब्बतियों ने दलाई लामा की वतन वापसी के विरुद्ध हाथ उठाये हैं।

उसी माह सरकार ने अपने खर्चे पर देश भर के सचिवों और लेखाकारों को गांसु के विभिन्न शहरों में आमंत्रित किया था। वहां से जाने से पहले उन लोगों को गांसु की राजधानी लांझोऊ में एक बैठक में शामिल होने को कहा गया और जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से उनसे परमपावन दलाई लामा की वतन वापसी का विरोध करने वाले आवेदन पर हस्ताक्षर करवाये गए। इस बैठक का प्रसारण स्थानीय टेलीविजन पर भी किया गया।

सुश्री होम्स ने बताया कि हेजुई के आमचोक शहर से आए एक वयोवृद्ध तिब्बती प्रतिनिधि ने जब इसपर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया तो उसे पीटते हुए वहां से ले जाया गया। इस बजुर्ग की इस तरह की जा रही पिटाई से खफा तिब्बती युवकों ने सचिवों और लेखाकारों पर उस वक्त हमला कर दिया जब वे लोग ग्येलमोगोन के रेस्तरां में खाना खा रहे थे।

सुश्री होम्स ने एक प्रत्यक्षदर्शी बौद्धभिक्षु के हवाले से बताया कि इस हमले की वजह से अनेक सचिव गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें गनान शहर स्थित अस्पताल ले जाया गया।

कैंपेन के प्रवक्ता मैट ह्विट्टिकेस ने बताया कि गांसु प्रांत में तिब्बतियों को सुअर का वध कर नया वर्ष मनाने को मजबूर किया जाता है, जबकि तिब्बतियों ने सुअर का वध नहीं करने का फैसला किया हुआ है क्योंकि परमपावन दलाई लामा का जन्म 'सुअर वर्ष' में हुआ था और वे लोग दलाई लामा के लंबे जीवन की अराधना करते रहे हैं।

चीनी अधिकारी वास्तव में दलाई लामा के विरुद्ध दुष्प्रचार अभियान को तेज करने में लगे हुए हैं। इस बारे में पूरे तिब्बत के मठों में रहने वाले भिक्षुओं और भिक्षुणियों को ऐसे बयान जारी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिनमें दलाई लामा की आलोचना की गई होती है।

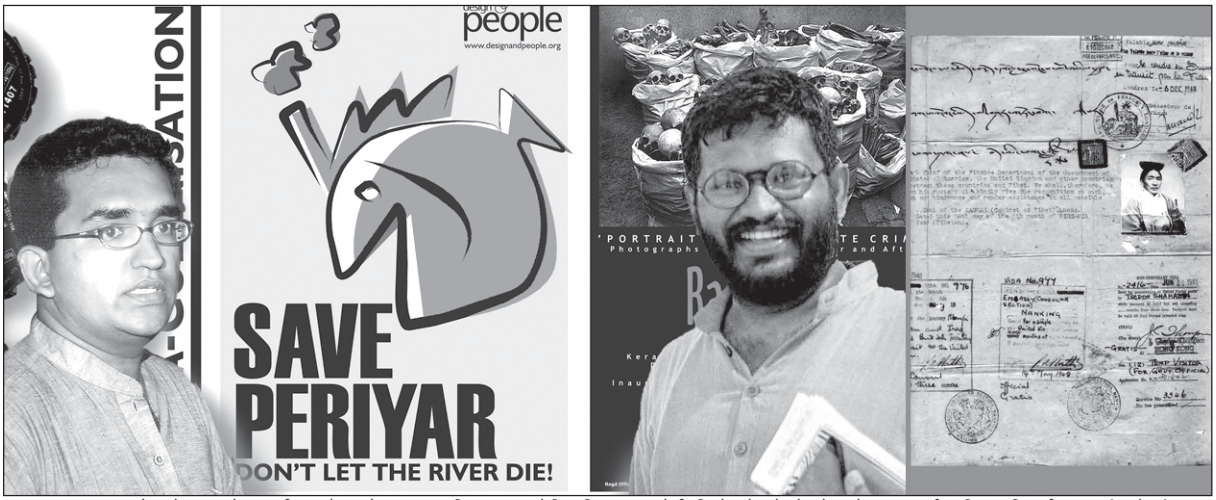

सुकु (बाएं) और सेतु अपने कार्यालय में। और स्वतंत्र तिब्बत का ऐतिहासिक पासपोर्ट जिसे खेजने में सेतु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई : सच्ची दोस्ती

एक सामान्य यात्रा से मजबूत हुई तिब्बतियों के प्रति आस्था

भारतीय जनता में तिब्बती आजादी की अलख जगाने में जुटे एक प्रमुख कार्यकर्ता सेतु दास

– शेवलिन सेबेस्टियन (इंडियन एक्सप्रेस से साभार)

1999 में उनके मन में 'फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत' नामक वेबसाइट शुरू करने का विचार आया। इसका पहला सदस्य उनका छोटा भाई सुकू (34) था, जो कोच्चि में रहता था और वास्तुकार था। बाद में यह संगठन पूरी तरह से एक तिब्बत समर्थक समूह बन गया।

कोच्चि, 7 जनवरी जाने–माने मलयाली कार्टूनिस्ट येसुदासन के पुत्र सेतुदास 1995 में छुट्टी बिताने जम्मू गये। वहां से उन्होंने श्रीनगर जाने का मन बनाया। पहले दिन तो बस आधे रास्ते गयी लेकिन भूस्खलन के कारण उन्हें बीच रास्ते से ही लौटकर जम्मू वापस आना पड़ा। दूसरे दिन एक आतंकवादी संगठन द्वारा सेना के दस्ते पर हमला करने के कारण रास्ता असुरक्षित घोषित कर दिया गया। इसलिए सेतुदास पंजाब, जम्मू–कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित पठानकोट बस अड्डे चले गये।

सेतुदास ने देखा कि धर्मशाला जाने वाली बस को छोड़कर सभी बसें खचाखच भरी थीं। मनमौजीपन में उन्होंने वहीं जाने का फैसला किया। उस वक्त तक उन्हें पता नहीं था कि धर्मशाला में परमपावन दलाईलामा और निर्वासित तिब्बत सरकार का मुख्यालय है। वहां पहुंचे तो लाखी रंग के चोगे पहने भिक्षुओं और भिक्षुणियों को इधर–उधर घूमते देखकर वह संशय में पड़ गए। पूछताछ की तो पता चला कि ये भोले–भाले दिखने वाले भिक्षु कभी राजनीतिक बंदी थे, जो चीनी उत्पीड़न के कारण तिब्बत से भागकर यहां आए हैं।

उन्होंने कहा, ''यह मेरे लिए आंख खोलने वाला था कि तिब्बत में इस तरह की भयावह स्थिति भी है।'' इस बात का खुलासा होने पर कि उनमें से करीब–करीब सभी लोग चीन की जेलों में उत्पीड़न के शिकार हुए थे, वह स्तब्ध रह गये।

सेतु ने कहा, ''एक भिक्षु ने मुझे अपना दाहिना हाथ दिखाया, जिसकी दो अंगुलियां काट दी गयी थीं।'' वहीं पर एक लंबा और सुन्दर काया वाला 70–वर्षीय वृद्ध व्यक्ति भी था, जिसका नाम था रेटिंग टेम्पा त्सेरिंग, जिसने चीन की जेलों में अपने जीवन के अनेक बसंत बिताये थे। वहां से भारत के लिए फरार होते वक्त उसपर गोलियां चलाई गयी थीं। सेतु ने कहा, ''उनमें से एक गोली त्सेरिंग की पीठ में घुस गयी थी।'' सर्जरी के माध्यम से गोली निकलवाने के लिए दलाई लामा द्वारा बार–बार कहे जाने के बावजूद त्सेरिंग ने ऐसा करने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि वह चीनी उत्पीड़न के सबूत के तौर पर यह गोली अपनी पीठ में ही रहने देना चाहते हैं।

इसी बीच तिब्बतियों के साथ हुए हादसे के बारे में अनभिज्ञ सेतु ने तिब्बत के पूर्व राजनीतिक बंदियों के संघ 'गु–चु–सुम' के सदस्यों से बातचीत प्रारंभ कर दी। उन्होंने इस मुद्दे पर वीडियो और अनेक पुस्तकें संग्रहीत की और उन्हें लेकर वह वापस मुंबई आ गये जहां वह डिजाइनर का कार्य करते थे। उसके बाद उन्होंने मुंबई से गु–चु–सुम के लिए चंदे की राशि भेजनी शुरू कर दी। वर्ष 1999 में उनके मन में 'फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत' नामक वेबसाइट शुरू करने का विचार आया। इसका पहला सदस्य उनका छोटा भाई सुकू (34) था, जो कोच्चि में रहता था और वास्तुकार था। बाद में यह संगठन पूरी तरह से एक तिब्बत समर्थक समूह बन गया। सेतु ने बताया, ''आज भारत में इसके 3900 सदस्य और 21 शाखाएं हैं और उरुग्वे, पाकिस्तान, नेपाल, स्पेन, श्रीलंका और ब्रिटेन में इसकी अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं स्थापित हो चुकी हैं।''

कोच्चि में 'फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत' का कार्यालय

चंगमपुझा कालोनी में है, जिसका संचालन सुकु करते हैं। यह कार्यालय छोटा लेकिन आरामदायक है। दीवार पर एक ब्लैकबोर्ड और तिब्बत के संबंध में अनेक पोस्टर हैं, जिनमें से एक पर यह पंक्ति लिखी गयी है– 'चीन, तिब्बत छोड़ो' सुकु ने कहा, ''हम पर्चे बांटकर, सार्वजनिक बैठकें आयोजित करके और विभिन्न तरह के अभियान चला कर लोगों में तिब्बत के प्रति जागरुकता लाने का प्रयास कर रहे हैं।'' हाल ही में शुरू किये गये अभियान का नाम है, 'तिब्बत के साथ दुनिया।' ये पोस्टकार्ड ऐसे हैं जिनपर दुनिया का नक्शा बना है, लेकिन इसमें कुछ फर्क है। नक्शे में तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के रूप में दर्शाया गया है।

जब सुकु से यह पूछा गया कि तिब्बत के मुद्दे पर कोच्चिवासियों की क्या प्रतिक्रिया होती है, तो उन्होंने कहा कि इसपर अलग–अलग प्रतिक्रियाएं आती हैं। जो लोग तिब्बत पर चीन के सैन्य नियंत्रण के बारे में जानते हैं वे कहते हैं, ''आप उस तिब्बत के लिए क्यों संघर्षरत हैं, जिसकी लड़ाई हम पहले ही हार चुके हैं।'' कुछ लोग यह पूछते हैं कि विदेशियों की ओर से संघर्ष करने की आवश्यकता क्या है, जब संघर्ष करने के लिए अपने ही देश में इतनी सारी समस्याएं हैं? सुकु कहते हैं, ''जब तक तिब्बतवासी भारत में रहते हैं और अपने वतन लौटने में अक्षम हैं, हम उनके अधिकारों के लिए लडते रहेंगे।''

तिब्बतियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोच्चि में संघर्षरत उनके एक और साथी वी जे जोस (52). प्रत्येक महीने बैठक आयोजित कराते रहते हैं, जिसमें वह तिब्बत में चीनी उत्पीड़न से संबंधित फिल्में दिखाते हैं और तिब्बत के इतिहास और पृष्ठभूमि के बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा कि फिल्में देखकर युवक तिब्बत में घटित घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं।

यदि आप इस संगठन की वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत डॉट ओआरजी) खोलें तो आपको चीनी सैनिकों द्वारा तिब्बती आंदोलनकारियों को दिये जा रहे मृत्युदंड की हृदयविदारक तस्वीरें देखने को मिलेंगी।

मुंबई में रह रहे सेतुदास कहते हैं, ''भारत की 54 तिब्बती बस्तियों में कुल एक लाख 30 हजार तिब्बतवासी निवास कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक दिन तिब्बत आजाद होगा और वे लोग अपने वतन लौट जाएंगे।'' हालांकि यह असंभव सपने जैसा प्रतीत होता है, लेकिन दास बंधु कोच्चि और देश के अनेक भागों में तिब्बत के मसले के लिए अपना संघर्ष जारी रखे हए हैं।

पांच तिब्बती संगठनों की तिब्बत की ओर कूच का एक दृश्य : वतन के लिए

पांच तिब्बती संगठन एक मंच पर आए

अहिंसक आंदोलन का फैसला, पहला ऐक्शनः भारत–तिब्बत सीमा तक शांति मार्च

फुर्बू थिनले

धर्मशाला, 25 जनवरी तिब्बतियों के पांच प्रमुख संगठनों ने तिब्बती आजादी के लिए संयुक्त रूप से आंदोलन चलाने का फैसला किया है। नवगठित इस मोर्चे ने निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे तिब्बतियों से अपील की है कि वे बीजिंग ओलम्पिक से पहले भारत–तिब्बत सीमा तक शांति मार्च में हिस्सा लें। इसके लिए दो पृष्ठों वाला पंजीकरण और घोषणा पत्र जारी किया है ताकि विरोध मार्च में हिस्सा लेने वालों का औपचारिक पंजीकरण शुरू किया जा सके।

आयोजकों ने आज संवाददाता सम्मेलन में पंजीयन प्रपत्र जारी करते हुए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी। पंजीयन कार्य 10 फरवरी तक चलेगा।

दो पृष्ठ के पंजीयन प्रपत्र में विरोध मार्च में शामिल होने वाले व्यक्ति को पूर्ण विवरण और परिवार के सदस्यों तथा रिश्तेदारों एवं नातेदारों के बारे में जानकारियां देनी होंगी तथा उस घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर करने होंगे जिसमें लिखा है कि मैं तिब्बतियों के इस आंदोलन में हिस्सा लेने की घोषणा करता हूं। घोषणा पत्र के अनुसार आयोजन समिति से सदस्यता की मंजूरी मिलने के बाद व्यक्ति को अहिंसक, शांतिपूर्ण और अनिश्चितकालीन आंदोलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बरकरार रखनी पड़ेगी और इसके नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।

इस शांति अभियान का शुभारम्भ चार जनवरी को दिल्ली में हुआ। पांचों समूहों ने यह भी कहा है कि यह आंदोलन निर्वासित तिब्बतियों की ओर से एक ऐसा

इस शांति अभियान का शुभारम्भ चार जनवरी को दिल्ली में हुआ। यह आंदोलन निर्वासित तिब्बतियों की ओर से ऐसा कदम होगा, जो तिब्बत की आजादी के आंदोलन को और मजबूती प्रदान करेगा। इन समूहों ने उम्मीद जताई है कि एकजुट आंदोलन से तिब्बत पर चीन के शासन का खात्मा हो जाएगा।

कदम होगा, जो तिब्बत की आजादी के लिए चलाए जा रहे आंदोलन को और मजबूती प्रदान करेगा। इन समूहों ने उम्मीद जताई है कि एकजुट आंदोलन से तिब्बत पर चीन के शासन का खात्मा हो जाएगा।

यह शांति यात्रा परमपावन दलाई लामा के निर्वासन स्थल धर्मशाला से 10 मार्च को शुरू होगी। उस दिन चीनी शासन के खिलाफ तिब्बतियों के राष्ट्रीय आंदोलन की 49वीं वर्षगांठ है। उनकी योजना भारत से तिब्बत की सीमा में प्रवेश करने और तिब्बत की राजधानी ल्हासा तक पहुंचने की है। इसके अलावा निर्वासित तिब्बती और उनके समर्थक ओलम्पिक मशाल दौड़ और बीजिंग ओलम्पिक में प्रदर्शन के लिए दुनिया भर में अहिंसक जनांदोलन शुरू करने की योजना बना रहे हैं।

आयोजकों ने दुनिया भर के निर्वासित तिब्बतियों से अपील की है कि वे 'तिब्बत शांति यात्रा' में शामिल हों और इसके समर्थन के लिए बीजिंग ओलम्पिक से पहले ज्यादा से ज्यादा विरोध प्रदर्शनों में भाग लें। आयोजकों ने चीनी नेतृत्व पर आरोप लगाया कि वह बीजिंग ओलम्पिक को तिब्बत में गैर–कानूनी चीनी शासन को वैधता दिलाने और अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता के लिए इसे एक बड़े मंच के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। आयोजकों ने यह भी आरोप लगाया कि करीब पांच दशक के दमन और सांस्कृतिक विनाश के बाद चीन के कब्जे वाले तिब्बत में स्थिति और भी बदतर हो रही है।

समूहों के चार जनवरी के बयान में कहा गया है कि इस जन आंदोलन की योजना 1959 में हुए राष्ट्रीय जन उभार की भावना से जुड़ी है और यह उन साहसिक तिब्बतियों की याद में है, जिन्होंने तिब्बत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।

यह शांति यात्रा परमपावन दलाई लामा के निर्वासन स्थल धर्मशाला से 10 मार्च को शुरू होगी। उस दिन चीनी शासन के खिलाफ तिब्बतियों के राष्ट्रीय आंदोलन की 49वीं वर्षगांठ है। उनकी योजना भारत से तिब्बत की सीमा में प्रवेश करने और तिब्बत की राजधानी ल्हासा तक पहुंचने की है। इसके अलावा निर्वासित तिब्बती और उनके समर्थक ओलम्पिक मशाल दौड़ और बीजिंग ओलम्पिक में प्रदर्शन के लिए दुनिया भर में अहिंसक जनांदोलन शुरू करने की योजना बना रहे हैं।

चीन के साथ तिब्बत का मुद्दा उठाएं भारतीय प्रधानमंत्री

धर्मशाला, 14 जनवरी निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे तिब्बतियों ने चीन के साथ तिब्बत का मुद्दा उठाने की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अपील की है। तिब्बतियों ने कहा है कि डॉ. सिंह की चीन यात्रा के दौरान अगर भारत चाहे तो तिब्बत मसले को सही तरीके से उठा सकता है।

'फ्री तिब्बत' की भारतीय शाखा के अध्यक्ष त्सेरिंग चोइंग ने कहा, ''तिब्बत का मसला भारत की ओर से विशेष रूप से उठाया जाना चाहिए क्योंकि सम्पूर्ण तिब्बत मुद्दे पर भारत का दांव अधिक लगा है।''

तिब्बतवासियों ने यह भी कहा कि भारत बातचीत के जरिये इस मसले के हल के लिए प्रयास कर सकता है। एक तिब्बती आंदोलनकारी लोबसांग वांग्याल ने कहा, ''आधिकारिक तौर पर पांच सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होंगे। लेकिन इनमें तिब्बत मुद्दे को पूरी तरह नजरंदाज किया गया है। तिब्बत मसले को दरकिनार करने से उसका हल नहीं होगा। तिब्बती ज्यादा की लालच नहीं करते, चीन के संविधान के तहत उनकी बहुत ही तार्किक मांग हैं। मेरा मानना है कि चीन को इसपर विचार करना चाहिए और भारत को इसके लिए दबाव बनाना चाहिए।''

चीन ने तिब्बत के पूर्व शासक और अध्यात्मिक नेता दलाई लामा से 1979 में सीधे सम्पर्क किया था। उनसे जारी बातचीत को 1993 में स्थगित कर दिया गया था। लेकिन धीरे–धीरे इस दिशा में प्रगति हुई है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि चीन दलाईलामा को लेकर अपनी नीति में धूतर्तापूर्ण, लेकिन महत्त्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।

उल्लेखनीय है कि अनुमानित एक लाख 34 हजार तिब्बती निर्वासन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर भारत और नेपाल में हैं।

काठमांडू तक जाएगी चीन की रेलगाड़ी : चीनी राजदूत

काठमांडू, 18 जनवरी। नेपाल टाइम्स ने चीनी राजदूत के साथ बातचीत की। इसमें तिब्बत में चीन की रेलगाड़ी को नेपाल तक लाने, माओवादियों के चीन के साथ रिश्ते और तिब्बत में नेपाली शरणार्थियों के सवाल पर विस्तृत चर्चा हुई।

नेपाल टाइम्स : क्या चीनी रेलवे को नेपाल की सीमा तक बढ़ाने की कोई योजना है। विदेश मंत्री ने अनेक मौकों पर यह मुद्दा उठाया है।

झेंग जियांगलिन : रेलवे लाइन ल्हासा में ही खत्म नहीं होगी, यह तिब्बत के अन्य शहरों तक पहुंचेगी। इस लाइन को नेपाल की सीमा तक बढ़ाए जाने की योजना है। भविष्य में रेलवे लाइन काठमांडू तक भी पहुंच सकती है।

एनटी : यह कबतक संभव हो पाएगा?

झेंग : फिलहाल कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। इसलिए इस बारे में मेरे पास बहुत अधिक जानकारी भी नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा समय लगेगा।

एनटी : कुछ लोग हैं जो यह दावा करते हैं कि चीन माओवादियों को गुप्त रूप से मदद कर रहा है।

झेंग : हम किसी एक पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। हमें लगता है कि किसी विशेष पार्टी के साथ गुप्त संबंध बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा उन सभी पार्टियों के साथ दोस्ताना और खुले रिश्ते होते हैं जो शांति और स्थायित्व के लिए काम करते हों और माओवादी भी इसी में से ही एक हैं।

एनटी : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होने के नाते, नेपाल में संयुक्त राष्ट्र मिशन की भूमिका और उसके फैसले के विस्तार पर चीन की क्या राय है?

झेंग : नेपाल में यूएन मिशन के मौजूदा आदेश का हम पूरा समर्थन देते हैं।

एनटी : अमरीका ने नेपाल में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों को पुनः पुनर्वास कराने को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की है। इसपर चीन क्या सोचता है?

झेंग : हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि तिब्बत अभी शांति, स्थायित्व और विकास की प्रक्रिया से गुजर रहा है। तिब्बत का मसला चीन का आंतरिक मामला है। हम किसी विदेशी ताकत को इसमें हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। दलाई लामा के गिरोह के साथ–साथ कुछ और संगठन हैं जो तिब्बतवासियों को अमरीका और यूरोप में बसाने और वहां बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के झूठ सपने दिखा रहे हैं। जो तिब्बती सच्चाई नहीं जानते और जो इन समूहों के झांसे में आ जाते हैं, वे नेपाल चले जाते हैं। उनमें से ज्यादा नाबालिग होते हैं। काठमांडू आने के बाद उन्हें हकीकत समझ में आती है। और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने तिब्बत लौटने के इरादे से हमारे दूतावास से सम्पर्क किया है। तिब्बती सरकार और चीन की जनता ऐसे अलगाववादी नेताओं को अपने इरादे में सफल नहीं होने देगी।

एनटी : नेपाल और भारत के बीच कालापानी सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत ने प्रस्ताव रखा है कि इसमें चीन को भी शामिल किया जाए क्योंकि यह क्षेत्र चीन की सीमा से भी सटा है। क्या चीन भी ऐसा ही सोच रहा है।

झेंग : भारत और नेपाल को अपने सीमा विवाद खुद ही सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लेना चाहिए।

अहमदाबाद में अहिंसा पर पांच दिवसीय आकर्षक तिब्बत महोत्सव

अहमदाबाद, 16 जनवरी गुजरात में अहमदाबाद के कनोरिया सेंटर ऑफ आर्ट्स में पांच दिवसीय 'तिब्बत अहिंसा महोत्सव' में तिब्बत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे।

इस महोत्सव का आयोजन केंद्रीय तिब्बत प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग (डीआईआईआर), कानोरिया सेंटर फॉर आर्ट्स, दर्पण एकेडमी एवं एलायंस फ्रांस डे' अहमदाबाद के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में डीआईआईआर से संबंधित मंत्री श्रीमती केसांग वाई ताकला ने कहा कि तिब्बत के पास विशेष प्रकार का अनुभव हैं। तिब्बत का संघर्ष दुनिया को यह बतलाता है कि हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हिंसा से निश्चित तौर पर 'और अधिक हिंसा' ही उत्पन्न होगी। उन्होंने कहा, ''यदि अहिंसा के रास्ते हम तिब्बती लोग अपने संघर्ष में बाजी मार लेते हैं तो दुनिया इस तथ्य को कबूल करेगी कि युद्ध का बेहतर विकल्प भी है। आज हिंसा से ग्रस्त दुनिया के लिए इससे अच्छा और कोई संदेश नहीं हो सकता। इसीलिए हम शेष दुनिया से अपील करते हैं कि तिब्बत का संघर्ष केवल तिब्बत की जनता का नहीं है। बल्कि इसमें बाकी दुनिया के सुखद भविष्य की कल्पना भी शामिल है।''

महात्मा गांधी की धरती पर इस तरह के महोत्सव के आयोजन की महत्ता पर जोर देते हुए कालोन केलसांग वाई ताकला ने कहा, ''यह शहर गांधी और अहिंसा की धरती है। यहां तक कि परमपावन दलाई लामा भी गांधी के सत्य–अहिंसा के पाठ से प्रेरित हैं। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है कि हम अहमदाबाद में यह महोत्सव आयोजित कर रहे हैं। इससे लोगों को हमारी संस्कृति और धरोहरों के बारे में जानने में मदद मिलेगी। इससे मातृभूमि के लिए हमारे अहिंसक संघर्ष के बारे में भी लोगों को जानने का मौका मिलेगा।''

महोत्सव की सह आयोजक दर्पण एकेडमी की निदेशक श्रीमती मल्लिका साराभाई ने कहा, ''किसी अन्य स्थान से अधिक, गुजरात को अहिंसा का संदेश दोहराने की जरूरत है।'' उन्होंने आगे कहा, ''आज की दुनिया के तथ्य बहुत ही भयावह हैं और उन्हें समझने की जरूरत है। हम तिब्बत के संघर्ष का समर्थन करते हैं और हमें अहिंसा के जरिये दुनिया को नये रास्ते पर लाया जाना चाहिए।'' महोत्सव के तहत दर्पण एकेडमी और कानोरिया संस्थान में भी अनेक प्रदर्शनियां आयोजित की गयीं।

यदि अहिंसा के रास्ते हम तिब्बती लोग अपने संघर्ष में बाजी मार लेते हैं तो दुनिया इस तथ्य को कबूल करेगी कि युद्ध का बेहतर विकल्प भी है। आज हिंसा से ग्रस्त दुनिया के लिए इससे अच्छा और कोई संदेश नहीं हो सकता। इसीलिए हम शेष दुनिया से अपील करते हैं कि तिब्बत का संघर्ष केवल तिब्बत की जनता का नहीं है। बल्कि इसमें बाकी दुनिया के सुखद भविष्य की कल्पना भी शामिल है।

कैमरे की

1. 22 जनवरी को दलाई लामा जी और पूर्व भारतीय राष्ट्रपति डा एपीजे ब
2. 22 फरवरी को तिब्बत के आम्दो प्रांत के रेबांग में चीन विरोधी प्रदर्शन क
3. तिब्बत के रेबांग आम्दो में चीन विरोधी प्रदर्शनों के समर्थन में 24 फरवरी
4. शोतोन समारोह के अवसर पर धर्मशाला के रंगमंच विद्यालय 'टीपा' में ना
5. ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर घोषित किया है
6. 20 फरवरी को सिचुआन के आबा क्षेत्र के एक मठ के समारोह में भाग ले
7. दुनिया भर की यात्रा पर निकली तिब्बती ओलंपिक मशाल सिडनी में 17
8. तिब्बत के रेबकांग में नववर्ष के मोनलम प्रार्थना समारोह में भाग लेते स्थ
9. भगवान बुद्ध की 34 जातक कथाओं के वार्षिक दीप महोत्सव में 21 फरव
10. वर्ष–2006 की मिस तिब्बत मेतोक ल्हांज़ी ने तिब्बती युवा कांग्रेस और सं

♦ आंखों देखी

आंख से

दुल कलाम ने ग्लोबल फाउंडेशन फार सिविलाइजेशन हिस्ट्री का उद्घाटन किया
ा दृश्य। इसमें चीन ने 200 से ज्यादा तिब्बतियों को गिरफ्तार किया।
को धर्मशाला में तिब्बती शरणार्थियों ने प्रकाश–यात्रा का आयोजन किया।
ाट्य समारोह के लिए आए दलाई लामा जी परंपरागत अभिवादन लेते हुए।
कि वह चीन सरकार से असहमति के कारण ओलंपिक समारोह में नहीं जाएंगे।
ेने वाले तिब्बती बच्चे अपनी खिलोना बंदूकों के साथ।
मार्च को पहुंची। इस अवसर मशाल रैली में तिब्बती और तिब्बत समर्थक।
नीय भिक्षु।
री की प्रार्थना सभा में परमपावन दलाई लामा।
ोनाम एंटरटेनमेंट के समारोह में नृत्य से समां बांध दिया। फोटोः तेनज़िन डासेल

फोटो : विजय क्रान्ति

पोताला के सामने पर्यटकों चीनी ताकत दिखाना सैनिक विमान : उपनिवेश की ऐंठ

तिब्बत में बढ़ते पर्यटन से चीन को आमदनी और प्रोपेगेंडा की सुविधा भी

तिब्बत में पर्यटन बढ़ने का असली फायदा चीन की टूरिस्ट कंपनियों को हो रहा है

गार्जियन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तिब्बत की आबादी से ज्यादा पर्यटक वहां पहुंचे हैं। इसकी वजह से तिब्बत की सड़कों, महलों और मठों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा है। फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत के प्रवक्ता मैट्ट विट्टिकेस ने कहा, ''इससे तिब्बत का पर्यावरण बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है।''

हाल के वर्षों में चीन ने तिब्बत को विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिया है और इससे वह लाखों डॉलर कमा रहा है। तिब्बत पिछले कई दशकों से सांस्कृतिक विध्वंस और मानवाधिकारों के उल्लंघन का केंद्र रहा है। अपनी खोई हुई छवि वापस लाने के लिए चीन अब तिब्बत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर कदम फूंक–फूंककर रख रहा है।

चीन के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि पर्यटन से तिब्बत को वर्ष 2007 में 4.85 अरब युआन (66.8 करोड़ अमरीकी डॉलर) का राजस्व हासिल हुआ है, जिसमें विदेशी पर्यटकों से हासिल होने वाला 1.3529 करोड़ अमरीकी डालर शामिल है। तिब्बत में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़कर 3,65,000 तक पहुंच गयी है, जो एक वर्ष पहले के आंकड़े से 2,10,500 अधिक है। चीन की सरकार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारी संवाद एजेंसी शिन्हुआ द्वारा हाल में जारी रिपोर्ट इस प्रकार हैं:

ल्हासा, 07 जनवरी (शिन्हुआ) तिब्बत की राजधानी ल्हासा के तीन प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर स्थलों का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण कार्य इस वर्ष पूरा हो जाने की संभावना है। यह जानकारी सांस्कृतिक अवशेषों से संबंधित क्षेत्रीय प्रशासन के सूत्रों ने दी है।

चीन की केंद्रीय सरकार ने पोटाला पैलेस, नोरबलिंका महल और साक्या मठ की मरम्मत के लिए 33.3 करोड़ युआन अर्थात् करीब 4.6 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किये हैं। इन स्थलों की मरम्मत का कार्य 2002 में शुरू हुआ था।

सांस्कृतिक अवशेष प्रशासन की निदेशक नीमा सेरिन्ग ने बताया, ''हमने परियोजना की कुल अनुमानित लागत का 77 प्रतिशत हिस्सा (यानी 25.672 करोड़ युआन) खर्च कर दिया है।'' सुश्री नीमा ने कहा, ''ये परियोजनाएं 2007 में ही पूरी होने वाली थीं, लेकिन पुनर्निर्माण कार्य की जटिलता और तिब्बत में विपरीत मौसम के कारण परियोजना पूरी होने में विलम्ब हो रहा है। हालांकि, हम मरम्मती कार्य इस वर्ष के अंत तक समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।''

सातवीं शताब्दी में निर्मित पोटाला पैलेस दुनिया की सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है, जबकि नोरबूलिंका, जिसका अर्थ तिब्बती भाषा में 'जवाहरात का पार्क' है, दलाई लामा का ग्रीष्मकालीन महल था। साक्या मठ बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकों और बहुमूल्य पेंटिंग के लिए मशहूर है। यह वहां का पहला तिब्बती मठ है और भारतीय बौद्ध शैली में बना है।

26 जनवरी को शिन्हुआ द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में वर्ष 2007 में विदेशी पर्यटकों की संख्या में 136 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गयी है।

क्षेत्रीय सरकार के पर्यटन ब्यूरो के उप–प्रमुख वांग सांगपिंग ने कहा कि पिछले वर्ष 3,65,000 विदेशी पर्यटक तिब्बत आए, जो पिछले वर्ष से 122 प्रतिशत अधिक है। वांग ने बताया कि पिछले वर्ष अमरीका के बजाय जापान से सर्वाधिक पर्यटक तिब्बत पहुंचे। जापानी पर्यटकों की संख्या 78,000 तक पहुंच गयी, जो 2006 के मुकाबले 5.2 गुना अधिक है। आंकड़े बताते हैं कि तिब्बत में अन्य हिस्सों से आए और विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या चार मिलियन से अधिक के रिकार्ड स्तर पर रही, जो 60.4 प्रतिशत की वार्षिक बढोतरी दर्शाता है। पर्यटन से तिब्बत का राजस्व 75.1 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़कर 4.85 अरब युआन अर्थात 66.8 करोड़ अमरीकी डालर पर पहुंच गया।

तिब्बत में पिछले वर्ष पर्यटन से हुई आय उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 14.2 प्रतिशत है, जो 2006 की तुलना में 4.6 प्रतिशत अधिक है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि तिब्बत में इस वर्ष पर्यटकों की संख्या पचास लाख के आंकड़े को भी पार कर जाएगी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक होगी। साथ ही पर्यटन राजस्व एक वर्ष पहले की तुलना में 24 प्रतिशत बढ़कर छह बिलियन युआन अर्थात 826 मिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है।

स्थानीय अधिकारियों का मानना है कि विदेशों में प्रचार–प्रसार अभियान चलाए जाने, चिंघाई–तिब्बत रेलवे की शुरुआत होने तथा न्यींगची में तीसरा

हवाईअड्डा शुरू होने की वजह से तिब्बत में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

गार्जियन में 14 जनवरी को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तिब्बत की जितनी आबादी है उससे अधिक पर्यटक वहां पहुंचे हैं। इसकी वजह से तिब्बत की सड़कों, महलों और मठों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा है। फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत के प्रवक्ता मैट्ट विट्टिकेस ने कहा, ''निश्चित तौर पर चीन के पश्चिमी क्षेत्र के विकास में पर्यटन एक स्तम्भ के रूप में है, लेकिन इससे तिब्बत का पर्यावरण बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है।''

शिन्हुआ के अनुसार हवाई अड्डों के निर्माण और रेल सम्पर्क के बावजूद पर्यटकों के दबाव से निपटने के लिए तिब्बत के पर्यटक स्थलों तक 775 पर्यटन बसें दौड़ रही हैं। वर्ष 2006 में शुरू हुए रेल सम्पर्क के माध्यम से प्रतिवर्ष 1.15 करोड़ से अधिक यात्रियों की आवाजाही होती है और तीन चौथाई माल ढुलाई भी इसी रेल के जरिये होती है।

अब न्गारी में चौथे हवाई अड्डे से उड़ान शुरू करने की बारी है, जो दुनिया का सर्वाधिक ऊंचा हवाईअड्डा होगा। तिब्बत क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासतों से राजस्व दोहन का चीन सरकार का प्रयास क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। सरकार का यह भी कहना है कि पर्यटकों की संख्या में बढोत्तरी से तिब्बत के प्राचीन स्मारकों को संरक्षित करने और वहां के निवासियों के जीवन का तौर–तरीका बदलने के लिए आवश्यक धन की उगाही में मदद मिलेगी। लेकिन विट्टिकेस ने कहा कि इससे तिब्बतियों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, ''तिब्बतियों को पीछे छोड़ दिया गया है और पर्यटन उद्योग का संचालन चीनी कंपनियों और वहां रह रहे हान समुदाय के लोगों द्वारा किया जा रहा है।''

तिब्बती जनता में इस बात पर भी चिंता है कि तिब्बत की संस्कृति चीन के हान समुदाय के लोगों की बढ़ती संख्या से प्रभावित हो रही है। निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे परमपावन दलाई लामा ने आरोप लगाया है कि चीन की सरकार तिब्बत की संस्कृति को नुकसान पहुंचा रही है और तिब्बत के पर्यावरण को खतरा पहुंचा रही है, जिसका दुष्प्रभाव न केवल तिब्बत पर पड़ेगा बल्कि यह भारत, बंगलादेश और खुद चीन को भी प्रभावित करेगा। आलोचकों का यह भी कहना है कि चीन सरकार तिब्बत में सरकारी प्रोपेगेंडा में प्रशिक्षित चीनी गाइडों के माध्यम से पर्यटकों की बढ़ती संख्या को तिब्बत के बारे में गलत जानकारी देने का अभियान भी चला रही है।

तिब्बत में चीनी रेल : तिब्बत का शोषण, भारत के लिए खतरा

चिंघाई–ल्हासा रेलवे की पहली फीडर लाइन का निर्माण कार्य शुरू होगा

भारत की सीमा सुरक्षा पर खतरा और गंभीर हुआ

बीजिंग, 19 जनवरी चिंघाई–ल्हासा रेलवे लाइन के ल्हासा और शिगात्से को जोड़ने वाली 254 किलोमीटर लंबी विस्तार परियोजना का निर्माण कार्य इस वर्ष शुरू होने की संभावना है। शिगात्से शहर भारत–नेपाल और भूटान की सीमा से सटा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञ इससे बहुत चिंतित हैं क्योंकि इससे चीन को भारत की सीमा तक भारी किस्म के हथियार और भारी संख्या में सेना को बहुत तेजी के साथ तैनात करने की अतिरिक्त सुविधा मिल जाएगी।

सरकारी मीडिया के अनुसार यह चिंघाई–ल्हासा रेलवे की पहली फीडर लाइन होगी और इसका निर्माण कार्य 1.42 अरब अमरीकी डालर की लागत से 2010 तक पूरा कर लिया जाएगा।

तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के अध्यक्ष क्विआंगबा पुनकॉग (जांपा फुंत्सोक) ने ल्हासा में बताया कि विस्तार लाइन के डिजाइन और भूमि अधिग्रहण आदि में विशेषज्ञ जुटे हुए हैं। दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर बनी 1956 किलोमीटर लंबी चिंघाई–ल्हासा रेलवे की औपचारिक शुरुआत जुलाई 2006 में की गयी थी। यह रेलवे लाइन फिलहाल चीन के चिंघाई प्रांत के सिनिंग शहर से चलकर तिब्बत की राजधानी ल्हासा तक फैली है।

सरकारी संवाद एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, जांपा ने कहा, ''चीन चिंघाई–ल्हासा रेलवे के विस्तार सहित दस प्रमुख निर्माण परियोजनाओं पर इस वर्ष 28 अरब युआन (3.7 अरब अमरीकी डॉलर) निवेश करेगा।''

शिगात्से भारत–नेपाल – भूटान सीमा से सटा है। रक्षा विशेषज्ञ हुत चिंतित हैं क्योंकि इससे चीन को इन देशों की सीमा तक भारी किस्म के हथियार और भारी संख्या में सेना को बहुत तेजी के साथ तैनात करने की अतिरिक्त सुविधा मिल जाएगी।

अवतारी लामाओं के पुनर्जन्म पर चीन ने कब्जा जमाने की नीति को दोहराया

सरकारी मंजूरी के बिना अवतारों को मान्यता नहीं

गत जुलाई में चीनी शासन ने ऐसे अवतारों की मान्यता रद्द करने की नीति की घोषणा की थी जिन्हें चीन सरकार से अवतारी होने की अनुमति न मिली हो। तिब्बतियों का कहना है कि इस कानून से न केवल तिब्बती संस्कृति की सदियों पुरानी परम्परा पर अंकुश लगेगा बल्कि भविष्य में नए अवतारी भिक्षुओं को चीन की नास्तिक कम्युनिस्ट पार्टी से अपने अवतार होने का सर्टिफिकेट हासिल करना होगा जो बहुत हास्यास्पद और निंदनीय है।

बीजिंग, 23 जनवरी एक समाचार के अनुसार चीन सरकार के सहयोगी एक वरिष्ठ तिब्बती लामा और चीन सरकार के सलाहकारों ने चीन सरकार की अनुमति के बगैर अवतारी लामाओं (चीनी परंपरा में ''लिविंग बुद्धा'') के नये अवतार लेने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विवादित कानून का बचाव किया है। उन लोगों का मानना है कि इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य 14वें अर्थात मौजूदा दलाई लामा के निधन के बाद अगले दलााई लामा के नाम की घोषणा करने के लिए चीन सरकार को सशक्त बनाना है।

गत वर्ष जुलाई में चीन के धार्मिक मामलों से संबद्ध प्रशासन ने ऐसे अवतारों की मान्यता रद्द करने की नीति की घोषणा की थी जिन्हें चीन सरकार से अवतारी होने की अनुमति न मिली हो। तिब्बतियों का कहना है कि इस कानून से न केवल तिब्बती संस्कृति की सदियों पुरानी परम्परा पर अंकुश लगेगा बल्कि भविष्य में नए अवतारी भिक्षुओं को चीन की नास्तिक कम्युनिस्ट पार्टी से अपने अवतार होने का सर्टिफिकेट हासिल करना होगा जो बहुत हास्यास्पद और निंदनीय है।

चीन की सरकारी संवाद एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार चीन सरकार के एक सहयोगी तिब्बती लामा थुपतेन कैझुब ने चीन सरकार के इन कानूनों का बचाव किया है। थुपतेन खुद भी एक 'लिविंग बुद्धा' हैं और चीन की क्षेत्रीय संसद के एक सलाहकार निकाय –तिब्बती पोलिटिकल कंसलटेटिव कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष भी हैं।

सिन्हुआ के अनुसार, चीन सरकार के सलाहकार निकाय के सदस्य सोईहाम रिनजिन ने भी अपने बयान में निर्वासन में रह रहे चौदहवें दलाई लामा की आलोचना की है। चीन सरकार इस बात से बहुत परेशान है कि तिब्बत से 50 साल बाहर रहने के बाद भी तिब्बतवासियों के मन पर उनका गहरा प्रभाव अभी भी बना हुआ है।

गत वर्ष पहली सितम्बर से अस्तित्व में आए अवतार संबंधी कानून के जरिये चीन से बाहर अवतारी बौद्धभिक्षुओं द्वारा जन्म लेने और इस बारे में धार्मिक मान्यता पाने पर भी चीन सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। चीनी की सरकारी वेबसाइट के अनुसार, तिब्बत और तिब्बतियों की आबादी वाले क्षेत्रों जैसे सिचुआन, चिंघाई, गांसु और युन्नान में 1991 से अब तक 1000 लिविंग बुद्ध चुने जा चुके हैं।

वर्ष 1989 में दसवें पंचेन लामा के निधन के बाद वर्ष 1995 में परमपावन दलाई लामा ने तिब्बत में ढूंढे गए छह वर्षीय गेदुन छयोकि नीमा को ग्यारहवें पंचेन लामा के रूप में अपनी मान्यता दी थी। लेकिन दलाई लामा के इस चुनाव के जवाब में चीन ने अपनी तरफ से एक अन्य बालक ग्याल्सेन नोरबू को पंचेन लामा का नया अवतार घोषित कर दिया। इसी के साथ दलाई लामा द्वारा चयनित बालक पंचेन लामा और उसके माता पिता को चीनी पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसे कहीं ऐसी जगह छिपा दिया कि उसका आज तक कोई अता–पता नहीं है। चीन के इस कदम की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने अपहृत पंचेन लामा को दुनिया का सबसे छोटा राजनीतिक कैदी करार दिया है।

चीनी सेना प्रमुख ने ताईवान, तिब्बत पर नेपाल की प्रशंसा की

बीजिंग, 09 जनवरी चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के प्रमुख और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय सैन्य आयोग के सदस्य जनरल चेन बिंगदे ने ताईवान और तिब्बत पर समर्थन के लिए नेपाल सरकार की प्रशंसा की है और आभार व्यक्त किया है।

जनरल बिंगदे ने चीन यात्रा पर आये नेपाली सेना के प्रमुख जनरल आर काटुवाल के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि चीन की सीमा नेपाल से लगती है और लंबे समय से दोनों देशों ने एक–दूसरे के साथ समानता, पारस्परिक लाभ पर आधारित सहयोग, एक दूसरे के प्रति सम्मान और दोस्ताना व्यवहार प्रदर्शित किये। दोनों देशों ने अनेक क्षेत्रों में सहयोग और आदान–प्रदान भी किये हैं।

उन्होंने कहा कि चीन और नेपाल के बीच दोस्ताना संबंध दोनों देशों की जनता के हित संरक्षित करते हैं। चीन की सेना नेपाल के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता को अत्यधिक महत्त्व प्रदान करती है और दोनों देशों की सेना के बीच सैन्य संबंधों को नयी ऊंचाई तक पहुंचाने और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता बरकरार रखने के लिए परस्पर सहयोग जारी रखने को वह और उनकी सरकार इच्छुक है।

जनरल काटुवाल ने कहा कि नेपाली सेना और जनता चीन के लोगों को तथा वहां की सेना को अपना वास्तविक हमदर्द समझती है और वे चीन द्वारा निरंतर दिये जा रहे बहुमूल्य सहयोग की सराहना करते हैं। नेपाली सेना पीएलए के साथ दौस्ताना संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान करने की इच्छुक है।

दो बौद्धभिक्षुओं की 'आत्महत्या' या हत्या?

चीनी शरारत का डर क्योंकि नए दलाई लामा की खोज में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती

धर्मशाला, 18 जनवरी (एशिया न्यूज)। तिब्बत के दूसरे सबसे बड़े शहर शिगात्से में पिछले दो महीनों में वयोवृद्ध तिब्बती बौद्धभिक्षुओं में से दो की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गयी। हालांकि आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि उनदोनों ने आत्महत्याएं की हैं। दोनों भिक्षु तिब्बतियों के अध्यात्मिक गुरू दलाई लामा के कट्टर समर्थक थे और ग्यारहवे पंचेन लामा को ढूंढने और निर्वासित दलाई लामा से उसकी मान्यता हासिल करने में उनका महत्वपूर्ण हाथ था।

इसकी पुष्टि अनेक भारतीय और तिब्बती स्रोतों ने भी की है, जो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। इन स्रोतों ने कहा, ''इन वरिष्ठ भिक्षुओं की मौत की यह खबर अब सामने आ रही है क्योंकि सरकार ने इसे छिपाने का प्रयास किया था।''

भिक्षु ग्यालत्सेन त्सेपा लोबसांग और यांगपा लोचो (दोनों 71–वर्षीय) को पंचेन लामा की गद्दी वाले मुख्य मठ 'ताशिलुंपो' में रहस्यमय परिस्थितियों में फांसी से लटका पाया गया था।

कुछ स्थानीय लामाओं ने बताया कि स्थानीय सरकार और मठ के कुछ सरकार समर्थक महंत उन दोनों भिक्षुओं को हमेशा प्रताड़ित करते रहते थे। उनकी गलती इतनी थी कि उन्होंने नब्बे के दशक के पूर्वार्द्ध में विद्रोह को उकसाने वालों को शिक्षा दी थी। साथ ही इनलोगों ने ग्यारहवें पंचेन लामा की पहचान में भी मदद की थी, जिसे बाद में चीनी पुलिस ने अगवा कर लिया था। यह वही मठ है जहां चीन के समर्थन में कोई भी कदम उठाने से इनकार करने और वहां के साम्यवादी अधिकारियों के खिलाफ कठोर बयान देने के तत्काल बाद 1995 में दसवें पंचेन लामा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गयी थी। चीनी जेल और लेबर कैंपों में कई साल तक रहने के बाद फिर से पुनर्स्थापित होने के बाद तब पंचेन लामा पहली बार अपने मठ शिगात्से की यात्रा पर आए थे।

मई 1995 में ताशिलुंपो मठ के कुछ भिक्षुओं (जिनमें आत्महत्या करने वाले दोनों भिक्षु शामिल थे) के विचार सुनने के बाद दलाई लामा ने छह–वर्षीय गेधुन छयोकी नीमा को नया पंचेन लामा नियुक्त कर दिया था। परमपावन दलाई लामा के अधिकारों को कमजोर करने के लिए चीन सरकार के धार्मिक मामलों के विभाग ने उसी वर्ष नवम्बर में एक अन्य छह–वर्षीय बालक ग्यालत्सेन नोरबू को नया पंचेन लामा नियुक्त कर दिय था।

बाद में दलाईलामा द्वारा चुने गए पंचेन लामा गेधुन को पुलिस ने अगवा कर लिया और उसके बाद से आज तक उनकी कोई खबर नहीं है। चीन उस बच्चे से मिलने के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आग्रहों को हमेशा से ठुकराता आया है। चीन सरकार का तर्क है कि गेधुन और उसके परिवारवाले बाहरी लोगों की वजह से परेशान होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसका गेधुन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

तिब्बतवासी चीन सरकार द्वारा चुने गये पंचेन लामा को पसंद नहीं करते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में पंचेन लामा दूसरा सबसे महत्त्वपूर्ण राजनीतिक–ध ार्मिक नेता होता है। वे दोनों एक दूसरे के अवतार को मान्यता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुरानी परम्परा के अनुसार जो भिक्षु पंचेन लामा की पहचान करते हैं, यदि वे जीवित हैं तो नये दलाई लामा की पहचान के लिए भी उनसे सम्पर्क किया जाता है। इसलिए भी इन दो भिक्षुओं की रहस्यमय तरीके से मौत के गंभीर अर्थ लिए जा रहे हैं।

सरकार और मठ के कुछ सरकार समर्थक उन दोनों भिक्षुओं को हमेशा प्रताड़ित करते रहते थे। उनकी गलती इतनी थी इनलोगों ने ग्यारहवें पंचेन लामा की पहचान में भी मदद की थी, जिसे बाद में चीनी पुलिस ने अगवा कर लिया था। पुरानी परम्परा के अनुसार जो भिक्षु पंचेन लामा की पहचान करते हैं, उन्हें नये दलाई लामा की खोज में भी शामिल किया जाता है। इसलिए इन` भिक्षुओं की रहस्यमय तरीके से मौत के गंभीर अर्थ लिए जा रहे हैं।

रजिस्ट्रेशन आफ न्यूजपेपर्ज ;सेंट्रल रूल्स 1956 के आठवें नियम के अंतर्गत 'तिब्बत देश' के स्वामित्व व अन्य विषयों संबंधी वक्तव्य :–

1. प्रकाशन का स्थान : 10–एच लाजपत नगर–3, नई दिल्ली–110024
2. प्रकाशन की अवधि : मासिक
3. मुद्रक : जमयांग दोरजी
   राष्ट्रीयता : भारतीय
   पता : 10–एच लाजपत नगर–3, नई दिल्ली–110024
4. प्रकाशक का नाम : जमयांग दोरजी
   राष्ट्रीयता : भारतीय
   पता : 10–एच, लाजपत नगर–3, नई दिल्ली – 110024
5. संपादक का नाम : जमयांग दोरजी
   राष्ट्रीयता : भारतीय
   पता : 10–एच, लाजपत नगर–3, नई दिल्ली – 110024
6. मालिक का नाम : जमयांग दोरजी

मैं, जमयांग दोरजी, यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गयी सूचनाएं मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

जमयांग दोरजी
दिनांक 1 फरवरी, 2008
प्रकाशक के हस्ताक्षर

1956 में भारत यात्रा के समय स्व. पंडित नेहरू और दलाई लामा : ऐतिहासिक संबंध

आखिर जिद्दी चीन के समक्ष झुकने को भारत मजबूर क्यों है ?

भारत गलतफहमियों में न रहे। चीन कभी भी भारत के खिलाफ कदम उठा सकता है

– ब्रह्म चेलानी

वर्ष 2007 की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि तिब्बत में मनमाने तरीके से गिरफ्तारियों और हिरासत के मामलों में 2006 की तुलना में तीन गुना वृद्धि हुई है। संगठन के अनुसार यह दिखाता है कि 2008 में होने वाले बीजिंग ओलम्पिक से पहले वहां मानवाधिकारों की स्थिति और भी बदतर हुई है।

नयी दिल्ली, 06 जनवरी ऐसे वक्त में जब चीन वियतनाम के कब्जे वाले द्वीप पर अपना अधिकार जताने से लेकर परमपावन दलाई के मुद्दे पर जर्मनी, कनाडा और अमरीका को आड़े हाथों लेकर अपनी सशक्त नीति पर अमल जारी रखे हुए है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चीन की यात्रा करने वाले हैं। डॉ. सिंह की यह यात्रा चीन के राष्ट्रपति हू जिंताओ की नवम्बर 2006 में हुई भारत यात्रा के दौरान किये गये उस समझौते का हिस्सा है, जिसमें दोनों देश नियमित सम्मेलन आयोजित करने को लेकर सहमत हुए थे।

श्री हू ने अपनी भारत यात्रा के साथ–साथ अपने मित्र देश पाकिस्तान की भी यात्रा की थी। इसका मतलब भारत को बताना था कि वह उसके खिलाफ पाकिस्तान के महत्व को समझते हैं। चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने 2005 में भी ऐसा ही किया था। लेकिन डॉ. सिंह केवल चीन की ही यात्रा करेंगे, वह जापान या वियतनाम नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यात्रा चीन के एक वर्ष से अधिक के उस प्रयास का नतीजा है, जिसके तहत वह दोनों देशों के बीच समता–संतुलन और भविष्य की सोच पर आधारित संबंध विकसित करना चाहता है।

चीन में दो चीजें घटित हुई हैं। पहला– चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद पर अपना रुख कड़ा कर दिया है और दूसरा– जैसा कि परमपावन दलाई लामा ने रोम में अपने हाल के संबोधन में उल्लेख किया है कि तिब्बत को लेकर चीन का रुख और कठोर होता जा रहा है। चीन दावा कर रहा है कि तिब्बत ऐसा कोई मसला नहीं है, जिसे हल किया जा सके।

भारत और चीन के बीच मतभेद का एक महत्त्वपूर्ण कारण तिब्बत का मुद्दा भी रहा है और चीन जबतक तिब्बत मसले के हल की प्रक्रिया शुरू नहीं करता तबतक चीन और भारत के बीच की खाई को पाटने की संभावना बहुत कम नजर आती है। चीन ने भारत के कुछ क्षेत्रों पर अपने दावे का आधार तिब्बतियों के धार्मिक संबंधों को बनाया है और खुद ही तिब्बत मसले को भारत–चीन के संबंधों के केंद्र में ला खड़ा किया है। यह बात और है कि परमपावन दलाई लामा ने चीन के दावों का खंडन किया। इसके बाद पसोपेश चीन ने अपने प्रतिनिधियों को वार्ता प्रक्रिया में यह मुद्दा उठाने के लिए उकसाया कि निर्वासित तिब्बत सरकार ने चीन के उस दावे का समर्थन किया है, जिसमें कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश पुराने तिब्बत का हिस्सा है। वस्तुतः तथ्य तो यह है कि तिब्बत पर चीन का दावा जितना संदिग्ध है, उससे दोगुना संदेहास्पद उसका भारत के कुछ हिस्सों पर किया गया दावा है।

चीन का सख्त और गैर–समझौतावादी रवैया भारत सरकार और परमपावन दलाई लामा के सहनशीलतापूर्ण रुख से बिल्कुल भिन्न है। भारत ने अनिर्धारित नियंत्रण रेखा पर चीन की आक्रामक सैन्य गतिविधियों को दरकिनार करने के लिए अपने कदम वापस ले लिये हैं। उधर दलाई लामा चीन से आजादी हासिल करने के लिए संघर्ष का रास्ता छोड़कर पीपुल्स रिपब्लिक के हिस्से के तहत स्वायत्तता के लिए तैयार होने के बावजूद उन्हें चीन से दो दशक में कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इस कारण दबी जुबान ही सही, परमपावन दलाई लामा को आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। जैसा कि दलाई लामा ने रोम में खुद ही स्वीकार किया था, ''हमारा दायां हाथ तो हमेशा चीन सरकार तक पहुंचता रहा है, लेकिन उसने हमें खाली हाथ ही लौटाया है।''

चीन के राष्ट्रपति हू जिंताओ की भारत यात्रा से पहले चीनी राजदूत के अरुणाचल प्रदेश पर विवादास्पद बयान से लेकर इसके विदेश मंत्री द्वारा मई 2007 में

दिये संदेश तथा भारत–तिब्बत सीमा पुलिस के प्रमुख द्वारा गत अक्टूबर में यह स्वीकार किया जाना कि चीनी सेना ने पिछले 12 महीनों में आकस्मिक हमले के 141 प्रयास किये हैं, भारत के प्रति चीन के कट्टर रुख में हो रही वृद्धि के उदाहरण हैं। गत वर्ष मई में चीन के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री को भेजे संदेश में कहा था कि चीन 2005 के सीमा समझौते से ज्यादा दिन बंधा नहीं रह सकता।

हालांकि चीन के बहुतेरे बुद्धिजीवियों को इस बात का भान है कि क्षेत्रीय विवादों के निपटारे के लिए भारत जितना उत्सुक है, उतना चीन इच्छुक नहीं है। चीन ने सैन्य आक्रमण या गुप्त अतिक्रमण के जरिये हड़प की गयी भूमि पर कब्जा बरकरार रखने के लिए भारत के कुछ और इलाकों पर भी दावा ठोंक दिया है, ताकि भारत को दबाव में रखा जा सके। इसी प्रकार, आजादी की मांग छोड़ने के बावजूद चीन दलाई लामा से संतुष्ट नहीं है। वह सार्वजनिक तौर पर दलाई लामा की उपेक्षा करता रहा है और बातचीत के लिए उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों की यात्रा को व्यक्तिगत यात्रा बताता रहा है। सभी लामाओं के पुनर्वतार पर सरकार की मंजूरी नितांत आवश्यक बनाकर चीन सरकार ने तिब्बत पर अपना शिकंजा और कस दिया है। इस आदेश से तिब्बतियों पर राजनीतिक उत्पीड़न तो फिर से बढ़ेगा ही, हान समुदाय के लोग तिब्बत की ओर रुख करने के लिए प्रोत्साहित भी होंगे।

ऐसे कई अवसर आए हैं जब भारत सरकार ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की युद्धक गतिविधियों के सबूत होने के बावजूद इसकी अनदेखी की है और वैसे समय में ऐसी गतिविधियों से इनकार किया है, जब उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उदाहरण के तौर पर पिछले माह सिक्किम–भूटान–तिब्बत की सीमा पर भारत की मानवरहित अग्रिम चौकी को पीएलए ने ध्वस्त कर दिया, लेकिन भारतीय थलसेना अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर ने इसे भूटान और चीन के बीच का मसला कहकर पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि भारत भूटान की रक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है।

यह महज संयोग नहीं है कि चीन ने तिब्बत में नयी रेल व्यवस्था, हवाईअड्डे और राजमार्गों सहित तमाम बुनियादी संरचनाओं का विस्तार किया है। रेलवे की वजह से चीन की त्वरित सैन्य तैनाती क्षमता बढ़ी है और इससे हिमालय के पार के सैन्य समीकरण बदल रहे हैं।

भारत की कुछ महत्त्वपूर्ण गलतियों की वजह से भी चीन को उसपर हावी होने का मौका मिला है। जुलाई 2003 में तत्कालीन प्रधानमत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी यात्रा के दौरान तिब्बत को चीन का हिस्सा बताकर चीन सरकार को बड़ी राहत प्रदान की थी, क्योंकि वह भारत से ऐसी ही स्वीकारोक्ति की अपेक्षा कर रही थी। श्री वाजपेयी ने तिब्बत मसले को सिक्किम से जोड़कर भी बहुत बड़ी गलती की। तिब्बत मुद्दे पर घुटने टेकने की वजह से भारत चीन के साथ क्षेत्रीय सीमा विवाद मामले में फायदा उठाने से वंचित रह गया। अब चीन ने अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा उठाया है और बड़ी चालाकी से सीमा विवाद के हल का दायित्व भारत के कंधे पर डाल दिया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को कम से कम तवांग पर अपना दावा छोड़ने को मजबूर करना है। तवांग मे तिब्बती नहीं रहते हैं, वहां मोन्पा नामक विशेष जनजाति का बसेरा है।

तिब्बत पर चीन के दावे का समर्थन कर भारत क्या चीन सरकार से किसी तरह का सार्थक और परस्पर स्वीकार्य हल प्राप्त कर सकता है? चीन की ओर से जो दबाव बनाया जा रहा है, उसे भारत की ओर से बनाया जाना चाहिए था। वर्ष 2006 से ही अरुणाचल के मुद्दे पर चीन का दावा गैर–नियोजित नहीं है। यह तो भारत की ओर से की गई गलतियों का मिलाजुला परिणाम है।

भारत चीनी दबाव से किसी तरह की राहत की अपेक्षा नही कर सकता, क्योंकि ताकत प्रदर्शित करने की चीनी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उपग्रह–विरोधी हथियार के परीक्षण, जिन–क्लास बैलेस्टिक मिसाइल युक्त पनडुब्बी, परमाणु क्षमता युक्त पनडुब्बी जैसी सैन्य सामग्रियां चीन की सैन्य ताकत को प्रदर्शित करती हैं। चीन के रवैये से ऐसी संभावना प्रतीत होती है कि वह किसी भी समय भारत–विरोधी कदम उठा सकता है।

कई बार ऐसा होता है कि तिब्बत समर्थक संगठनों द्वारा आयोजित कुछ कार्यक्रमों की रिपोर्टें न उपलब्ध होने के कारण 'तिब्बत देश' में प्रकाशित होने से रह जाती हैं। आयोजकों से अनुरोध है कि वे कार्यक्रमों की रिपोर्ट और कुछ फोटो की फाइलें (लगभग 500 kb) हमें इस ई–मेल पते पर अवश्य भेजें :

tibbatdesh@yahoo.com

यदि ई–मेल न संभव हो तो इस पते पर भेजें :
'तिब्बत दे□ा', भारत–तिब्बत समन्वय केंद्र, 10-H लाजपत नगर–3, नई दिल्ली–110024

भारत की कुछ महत्त्वपूर्ण गलतियों की वजह से भी चीन को उसपर हावी होने का मौका मिला है। तिब्बत पर चीन के दावे का समर्थन कर भारत क्या चीन सरकार से किसी तरह का सार्थक और परस्पर स्वीकार्य हल प्राप्त कर सकता है? चीन की ओर से जो दबाव बनाया जा रहा है, उसे भारत की ओर से बनाया जाना चाहिए था। वर्ष 2006 से ही अरुणाचल के मुद्दे पर चीन का दावा गैर–नियोजित नहीं है। यह तो भारत की ओर से की गई गलतियों का मिलाजुला परिणाम है।

फोटो : विजय क्रान्ति

भारतीय धर्मगुरुओं के साथ दलाई लामा : आपसी श्रद्धा का संबंध

गांधी को मैं अपना गुरु मानता हूं

गुजरात विद्यापीठ और आईआईएम के छात्रों से दलाई लामा की मुलाकात

'नैतिकता को बरकरार रखकर आप अपना कारोबार करते हैं या कंपनी चलाते हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यह मानवता का ही एक अंश है। कोई माने या न माने पर नैतिकता बरकरार रखने से आपको कारोबार में सफलता भी मिलेगी और शांति भी।

अहमदाबाद, 20 जनवरी तिब्बत के निर्वासित शासक और सर्वोच्च अध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने कहा है कि उनके गुरु बुद्ध और गांधी भारत से हैं जबकि भारतीयों के भगवान शिव का घर तिब्बत में है।

गुजरात विद्यापीठ के ठसाठस भरे ऑडिटोरियम में उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए परमपावन दलाई लामा ने कहा, ''मैं गांधी का अनुयायी हूं और बहुत बड़ा प्रशंसक भी। हालांकि मुझे गांधीजी से मिलने का कोई अवसर नहीं मिला, लेकिन अपने ख्वाब में मैं उन्हें आधुनिक युग का गुरु मानता हूं।''

इस अवसर पर विद्यापीठ के कुलाधिपति नारायणभाई देसाई एवं कुलपति सुदर्शन अयंगार भी मौजूद थे। नोबल शांति पुरस्कार विजेता दलाई लामा ने इस अवसर पर मृणालिनी साराभाई द्वारा लिखित पुस्तक 'मोहनदास करमचंद गांधी फॉर चिल्ड्रेन' का विमोचन भी किया।

परमपावन दलाईलामा ने कहा, ''आज के युग में प्राचीन चिंतन को पुनर्जीवित करने और उसे आगे बढ़ाने में विद्यापीठ जैसे संस्थान महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अहिंसा राजनीतिक संदेश बन चुका है। सबसे पहले भारत ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था और बाद में दुनिया के अन्य देशों तक इसका प्रचार–प्रसार हुआ। हालांकि यहां से अब समाप्त होने के कगार पर है। इसे फिर से जीवित कीजिए, यह मेरा आग्रह है।''

अपनी अहमदाबाद यात्रा के दौरान दलाई लामा वहां के सुप्रसिद्ध शिक्षा केंद्र भारतीय प्रबंधन संस्थान भी गए। संस्थान का मुख्य हाल विद्यार्थियों से खचाखच भरा था। यह संस्थान मैनेजमेंट ट्रेनिंग के क्षेत्र में न केवल भारत में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ चर्चा में उनका मुख्य विषय काफी हद तक व्यापार और व्यवसाय में नैतिक मूल्यों के स्थान पर केंद्रित रहा।

मंच पर रेमण्ड ग्रुप के मालिक विजयपत सिंघानिया और पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी के साथ विराजमान परमपावन दलाई लामा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए धन महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए नैतिकता को तिलांजलि देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने कहा, ''नैतिकता को बरकरार रखकर आप अपना कारोबार करते हैं या कंपनी चलाते हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यह मानवता का ही एक अंश है। कोई माने या न माने पर नैतिकता बरकरार रखने से आपको कारोबार में सफलता के अलावा मन–मस्तिष्क को भी शांति मिलती है। नैतिकता और सफलता एक–दूसरे के विरोधाभासी नहीं, एक–दूसरे के पूरक हैं।''

अपने व्याख्यान के बाद नोबल पुरस्कार विजेता दलाई लामा ने संस्थान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के साथ भी सीधे–सीधे बातचीत की। इस अवसर पर आईआईएम के छात्र वैभव बिल्मोरिया की टिप्पणी थी, ''दलाई लामा ने कार्यस्थल पर नैतिकता बनाये रखने पर जोर दिया। दलाई लामा ने इसे एक ऐसा विचार बताया जिसपर समूचे कॉरपोरेट जगत में अमल की जरूरत है।''

आईआईएम के आज के स्नातकों के लिए, जो कल के प्रबंधक बनने जा रहे हैं, क्लासरूम का यह सत्र पूरी तरह भिन्न था। यह देखना सुखद होगा कि इन विद्यार्थियों ने दलाई लामा के इस व्याख्यानमाला से कितना कुछ आत्मसात किया और कितना इसपर वे अमल कर पाएंगे।

दलाई लामा की पांच दिन की यात्रा का मुख्य आकर्षण अहिंसा महोत्सव था जिसका आयोजन कनोरिया आर्ट सेंटर में किया गया।